International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.9 Issue. 3 Jan-Feb-2022

डिजिटल अर्थव्यवस्था : अवसर एवं चुनौतियाँ

डा० सुरेखा पिपलानी
एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
जी०यू० (पी०जी०) कालेज, बहेड़ी (बरेली)ए सम्बद्ध: एम०जे०पी रूहेलखण्ड वि०वि०, बरेली

सार-संक्षेप

भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूप में परिर्वतन पारम्परिक अवधारणाओं को बदल रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के द्वारा विगत कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक गतिविधियों में तीव्र विकास की प्रवृति दृष्टिगोचर हो रही है। वर्तमान में डिजिटल तकनीक एक सामान्य उद्देश्य के रूप में उभर रही है। ऐसे कई क्षेत्र जो अभी तक तकनीकी रूप से अछूते थे, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य होना असम्भव था लेकिन अब तकनीकी विकास की मदद से वहाँ भी घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के कारण विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन में भी सरलता और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था की डगर आगे बढ़ रही है। वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रगति का पर्याय बन चुकी है।

मुख्य शब्द:- डिजिटल, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, विकास।

प्रस्तावना

प्रौद्योगिकी ने भारत को बदलने का अवसर प्रदान किया है। देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिये प्रौद्योगिकी अपनाने की दशा में आमूल-चूल परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। इन बड़े बदलावों में मोबाइल नैटवर्क का फैलाव प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सरकार ने एक मजबूत, सुरक्षित तथा अखिल भारतीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तन्त्र स्थापित करने की दिशा में केन्द्रित पहल की है जिससे इसके लाभ देश के समस्त वर्गों तक पहुँचाये जा सकें। निरन्तर परिवर्तित हो रही जीवनशैली तथा प्रौद्योगीकरण के कारण वर्तमान समय में कम्प्यूटर समर्थित प्रौद्योगिकियों पर आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकियों पर आधारित होती है। यह इंटरनेट के माध्यम से भौतिक व्यवसायों को सहजता से संचालित करने के लिये नये उपकरण प्रदान करती है। इस वैब आधारित अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन-देन क्रेडिटकार्ड, डेबिटकार्ड, इण्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेन्ट तथा अन्य डिजिटल तरीकों से किया जाता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के घटक

परिवर्तित होते परिदृश्य के आधार पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य घटक हैं-

डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे पहला घटक डिजिटल आधारभूत संरचना है। डिजिटल आधारभूत संरचना अर्थात् भारत के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल सेवाऐं पहुँचाने के लिये एक मजबूत और बुनियादी ढाँचा तैयार करना। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही साथ वित्तीय

समावेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। हाई स्पीड वाई-फाई सहित डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने की योजना ने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का दूसरा मुख्य घटक डिजिटल सेवा का वितरण करना है। तकनीकी रूप से समझदार युवा पीढ़ी वस्तुओं की खरीद का सबसे सरल माध्यम ऑनलाइन खरीद को ही मानती है। जिससे देश में ई. कॉमर्स तथा एम. कॉमर्स का विस्तार हुआ है। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अर्न्तगत हुए उल्लेखनीय सुधारों में से एक सरकारी ई. मार्केट प्लस है जो सरकारी खरीद के लिये एक पोर्टल है जहाँ M.S.M.E को क्रय गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर आंकड़ों की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार के आंकड़ों को समझने और विश्लेषण करने के दौर से गुजर रही है। इसी के आधार पर भारत सरकार ने अपना स्वयं का डेटा पोर्टल लॉन्च किया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था - एक अवसर

तकनीकी प्रसार के साथ भारत आर्थिक विकास के आधार पर समृद्धि की राह पर अग्रसर है। एक लम्बे समय से देश जिन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था, डिजिटल तकनीक के द्वारा उन अवरोधों को उत्तरोत्तर समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नि:सन्देह कोविड-१९ के दौरान देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, परिणामस्वरूप परम्परागत रूप से की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों में लगने वाला समय, धन और श्रम में बचत होती हुई दिखायी दे रही है। इण्टरनेट तक पहुँच और आय स्तर में वृद्धि के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष २०३० तक ८०० अरब डालर का स्तर पार कर सकती है। स्मार्ट फोन, इन्टरनेट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, सेंसर आदि तकनीकों के तेजी से विकास से डिजिटलीकरण प्रगति की ओर अग्रसर है। देश अपनी महान सांस्कृतिक परम्पराओं को तकनीक के साथ जोड़कर एक आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल तकनीक के उपयोग से अर्थव्यवस्था नई ऊँचाइयाँ छू रही है। वर्क फ्रॉम होम तथा आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलने से भारत के डिजिटल कारोबार का महत्व बढ़ा है। विश्व की प्रसिद्ध कम्पनियों के साथ ही अमेरिका की टैक कम्पनियाँ भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा खुदरा क्षेत्र के ई.कामर्स बाजार में निवेश के लिये आगे बढ़ी हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का एक मुख्य कारण यह भी है कि मोबाइल और डेटा पैक सस्ता होने के कारण इन्टरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मोबाइल ब्राडबैण्ड इण्डिया ट्रैफिक (एमबीट) इण्डेक्स २०२१ के अनुसार डेटा उपयोग बढ़ने की रफ्तार सबसे अधिक भारत में है।

वैश्विक डिजिटल कम्पनियों पर लगाये गये करों के द्वारा देश की आय में वृद्धि हो रही है। ई. कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ डिजिटल सेवा कर (डी.एस. टी.) राष्ट्रीय आय का नया स्रोत बनता जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ डिजिटल सेवा कर की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। बजट २०२२ में वर्चुअल डिजिटल करेन्सी पर बड़ा फैसला किया गया है। डिजिटल परिसम्पत्ति का स्थानान्तरण करने पर ३० प्रतिशत कर देना होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ देश में नवीन रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। विश्व विख्यात मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित की गयी रिपोर्ट, 'डिजिटल इण्डिया : टैक्नोलॉजी टू ट्रान्सफार्म ए कनेक्टेड नेशन' में कहा गया है कि जहाँ भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्ष २०२५ तक लगभग ६ से ६.५ करोड़ रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे, वहीं डिजिटलीकरण के कारण लगभग ४ से ४.५ करोड़ परम्परागत रोजगार समाप्त हो सकते हैं। देश में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के कारण कई क्षेत्रों के रोजगार तेजी से समाप्त हो रहे है, जबकी दूसरी तरफ डिजिटल क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को और अधिक बल प्रदान करने के लिये बजट २०२२ में कई प्रावधान गये हैं। डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के प्रसार के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के ७५ जिलों में ७५ डिजिटल बैंको की स्थापना करेंगें। कोर बैंकिंग से १,५०,००० डाकघरों को जोड़ा जायेगा। बैंक से डाकघर के खाते में पैसा ऑनलाईन स्थानान्तरित किया जा सकेगा। ए.टी.एम. की सुविधा डाकघरों के लिये भी उपलब्ध होगी। डिजिटल भुगतान एक प्रकार से डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का ही विस्तार है, इसमें वित्तीय लेन–देन को औपचारिक रूप दे कर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों में भुगतान के पारम्परिक तरीके बाधित होने के कारण डिजिटल लेन-देन सेवाओं का उपयोग बहुत बढ़ गया है। डिजिधन मिशन का प्रारम्भ जून २०१७ में भारत सरकार द्वारा किया गया, जिससे सभी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सके। उद्योग संगठन और पी.डब्ल्यू.सी. की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०२३ तक देश में डिजिटल भुगतान में वार्षिक २० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। वर्ष २०१९ के अन्त तक भारत में डिजिटल लेन-देन लगभग ६४.८ अरब डॉलर रहा है और यह वर्ष २०२३ तक दोगुना से अधिक बढ़कर लगभग १३५.२ अरब डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है। बैंको में डिजिटल लेन-देन, करदाताओं द्वारा करों के ऑनलाइन डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन क्रय -विक्रय ने अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र भी अपनी आगतों व बाजार के लिये डिजिटल हो रहा है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और कीट नाशकों के प्रसार हेतु कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूअभिलेखों के डिजिटलीकरण से कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कार्यकरण में तीव्रता एवं सरलता देखने को मिल रही है। भूअभिलेखों के डिजिटलीकरण से किसानों को कृषि सम्बन्धी विभिन्न सेवाऐं ऑनलाइन प्रदान की जायेंगी। सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों के लिये उनके द्वारा क्रय की गई सामग्री हेतु पेपरलैस एण्ड टू एण्ड ऑनलाईन ई-बिल प्राणाली शुरू होगी।

इस प्रकार कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में क्रेडिटकार्ड, डेबिटकार्ड, ई-पेमेन्ट, मोबाइल-बैंकिग आदि का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ई.कामर्स तथा एम.कॉमर्स व्यवसाय के क्षेत्र में एक समानान्तर क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। नये स्टार्टअप प्रतिदिन खुल रहे हैं और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती व्यापारिक सम्भावनाओं के बीच दुनियाभर की बड़ी-बड़ी

ऑनलाइन कम्पनियों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक संगठनों द्वारा भी स्थानीय किराना दुकानों व कारोबारियों को ऑनलाइन जोड़ने के प्रयास की नई रणनीति बनाई जा रही है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में जैसे-जैसे अवसरों मे वृद्धि होती है, वैसे-वैसे ही चुनौतियाँ भी दस्तक देती हैं। यद्यपि विभिन्न प्रोत्साहनों के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ रही है लेकिन अभी भी इसके तीव्र विकास में आने वाली अनेक बाधाऐं एवं चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना हम सभी को मिल कर करना है।

प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना होगा और साथ ही डिजिटलीकरण के लिये आधारभूत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की कमी बनी रहती है परिणामस्वरूप मोबाइल ब्रॉडबैंड की उचित स्पीड नही मिलने के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास बाधित होता है। अत: इस बाधा को दूर करने के लिये सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त पहुँच बनानी होगी। इण्टरनेट के प्रयोग को सभी के लिये सुलभ कराने हेतु अबाध विद्युत आपूर्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। पी.सी.ओ. की तरह ही पब्लिक इण्टरनेट एक्सेस प्वाइंट की व्यवस्था सुदृढ़ बनानी होगी। देश में अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अभी भी डिजिटल बैंकिग व्यवस्था की दृष्टि से पीछे है अनेक बार स्मार्ट फोन, बैंक खाता तथा क्रेडिट/डेविट कार्ड की सुविधा न होने के कारण ग्रामीण जनता के द्वारा ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पाता, इसलिये डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को उत्तरोत्तर गति देने के लिये इन सुविधाओं को बढ़ाने के अभियान में अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही ग्रामीण जनता के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था हेतु विश्वास जाग्रत कर उन्हें पारम्परिक लेन-देन के स्थान पर डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाने के लिये प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों को रोकने के लिये सरकार द्वारा साईबर सुरक्षा मजबूत करने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगें क्योंकि डिजिटल भुगतान के समय होने वाली धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारण लोगों का ऑनलाइन लेन-देन में विश्वास कम बना रहता है।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिये मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिये युद्धस्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। भारत विश्व में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है इसलिये बदलते परिवेश के अनुसार इस युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक से सम्बन्धित रोजगार योजनाओं में दक्ष करना होगा। उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी विधाओं में पारंगत होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा एवं कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, तकनीकी कुशलता, विज्ञापन क्षेत्र, वैब डिजायनिंग, सोशल मीडिया, वैब सम्बन्धित सॉफ्टवेयर का ज्ञान, विश्लेषणात्मक तथा अनुसंधानात्मक कौशल के साथ देश दुनिया की जरूरतों के अनुसार स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसी ही तैयारी के साथ युवा पीढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था में छिपे अवसरों को खोजकर आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है।

निष्कर्ष

नि:सन्देह डिजिटल अर्थव्यवस्था मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। जब भी एक पारम्परिक अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित होती है तो वह अवसरों के साथ कई चुनौतियाँ भी ले कर आती है। बजट प्रावधानों के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के योगदान को स्पष्ट मान्यता मिलेगी तथा आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण सृजित होने वाले नये रोजगार के अवसर और आर्थिक उपलब्धियाँ भारतीय युवाओं को प्राप्त होंगी।

सन्दर्भ सूची:

1. https//: yojana.gov.in
2. www. kurukshetramagazine.gov.in
3. www. Aajtak.in
4. https//: hindigadgets360.com.india
5. https//:zeenews.india.com.national
6. https//:amarujala.com
7. https//:digitalindia.gov.in